पंजाब के समक्ष वित्तीय संकट

3454. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले दशक के दौरान पंजाब प्रशासनिक व्यय में बढ़ोतरी हो जाने के कारण, पंजाब सरकार पर लगभग 4,200 करोड़ रुपये का ऋण हो गया है,

(ख) क्या यह भी सच है कि इस ऋण को निर्धारित अवधि में लौटाने के बारे में पंजाब सरकार ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है,

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार, पंजाब सरकार को इस वित्तीय संकट से निपटने में मदद करने के लिये उसे विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोट्दुखे): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने नवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार ऋण राहत सहित एकमुश्त उपायों को अन्तिम रूप दिए जाने तथा एक अन्तरिम उपाय के रूप में कम से कम आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए विशेष अवधि ऋणों के बारे में स्थगन मंजूर करने का अनुरोध किया है।

(ग) 1991-92 के दौरान पंजाब को 600 करोड़ रुपए का विशेष योजनागत ऋण दिया गया है। इसके अलावा, राज्य की वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए तथा राज्य को ऋण-राहत दिए जाने के बारे में नवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए पंजाब सरकार को 1990-91 तक दिए गए विशेष ऋणों के बारे में मूल तथा उस पर ब्याज की अदायगी पर चालू वित्तीय वर्ष तक के ऋण-स्थगन की इजाजत दी है। इस ऋण-स्थगन के कारण 1991-92 में कुल 542 करोड़ रुपए की वित्तीय राहत प्रदान की गई है।

(घ) ऊपर (ग) में दिए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Rupee Financing to Indian Projects by World Bank

3455. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the World Bank has agreed to extend Rupee financing to Indian projects;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) if not, whether Government propose to seek execptional financing support from the World Bank; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) This is still at the proposal stage.

(c) Yes, Sir.

(d) The exact quantum of exceptonal financing will be decided at the Air-India Consortium meeting.

ADBs Loan for Hydro Carbon Sector

3456. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Asian Development Bank has approved a substantial loan in US dollars for the development of hydro carbon sector in the country;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) how Governmnet propose to utilise the loan amount in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR: (a) Yes, Sir.

(b) The Asian Development Bank has extended a loan facility of US $ 250 million for the development of Hydro Carbon Sector Programme in the country. The proceeds of the loan are expected to be utilised by 31st December, 1994. The repayment of the loan is to be made by 15th December, 2006.

(c) The loan would provide Balance of Payment (BOP) support and would be used primarily for financing of imports of fertilisers newsprints, edible oils, stainless steel, coking coal and petroleum products and other essential goods.